हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 22 जनवरी 2025, समय 1305 (05 मिनट)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** अभियान के दस वर्ष पूरे होने पर कहा है कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से स्त्री-पुरूष के बीच का विभेद कम हुआ है तथा बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए उचित माहौल सृजित हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस अभियान से उन जिलों में भी लिंगानुपात में सुधार हुआ है जहां इसमें काफी अंतर होता था। उन्होंने कहा कि इस अभियान से स्त्री-पुरूष समानता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। श्री मोदी ने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें।

****

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने कहा कि 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** योजना प्रदेश में मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना से प्रदेश में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बनी और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपनी मेहनत और मेधा से इतिहास रच रही हैं। उन्होंने कहा कि **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** योजना ने हरियाणा में लड़कियों के जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार लाने और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है । इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात साल 2024 में बढ़कर 910 हो गया है। मंत्री ने कहा कि लिंगानुपात में सुधार के लिए चिकित्सकों , झोलाछाप चिकित्सकों और दलालों की अवैध गतिविधियों को रोका गया है और 4 हज़ार गिरफ्तारियां की गई है ऐसे ही आगे भी कार्रवाई जारी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यह फ़ैसला लिया है कि **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** योजना के तहत महिला सरपंचों को उनके गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकें।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए 3 करोड़, 87 लाख से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिए 35 लाख रूपये की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इनकी स्थापना से, सभी जिलों में अपनी अलग स्थायी लोक अदालत होगी। वर्तमान में, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल

और पलवल में कैंप कोर्ट आयोजित किए जा रहे हैं। जबकि चरखी दादरी एकमात्र ऐसा जिला है, जहां कोई नियमित/कैंप कोर्ट आयोजित नहीं किया जा रहा है। इसलिए, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल जिलों के लिए 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की अनुमति दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि इन जिलों में अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों के पदों के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जिसमें प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए एक-एक अध्यक्ष, रीडर, स्टेनो टाइपिस्ट और दो-दो सदस्य, प्रोसेस सर्वर्स और चपरासी के पद शामिल हैं।

****

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज गुरुग्राम में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने नागरिकों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम सहित प्रदेश के बाकी हिस्सों में वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है जिसमें दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि दिन -प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्य मार्गों पर हर निश्चित दूरी पर एक ट्रामा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है । उन्होंने लोगों को दुर्घटना में घायल होने वालों की तुरंत सहायता करने का आह्वान किया। इस दौरान कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि रेवाड़ी में एम्स का निर्माण कार्य जोरों पर है और अप्रैल माह तक उसमें ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाने की उम्मीद है।

****

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में कल साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर पंचकूला में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिस में बैंकिंग सेक्टर तथा फिनटेक कंपनियों के साथ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कांफ्रेंस में आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सहित देशभर के लगभग 50 बैंकों तथा गूगले पे, पेटीएम, अमेज़न पे तथा फोन- पे जैसी फिनटेक कंपनियों के बड़े अधिकारियों व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर श्रीमती ममता सिंह और ,पुलिस महानिरीक्षक, शिवास कविराज ने हिस्सा लिया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि साइबर अपराध संबंधी चुनौतियां से निपटने के लिए सभी को मिशन मोड पर पूरी लगन से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को बैंक खातों में संदिग्ध रूपयो के लेनदेन एवं नकली बैंक खातों पर नजर रखने और उस पर उचित कार्रवाई करने को कहा। श्री कपूर ने RBI के नए दिशा निर्देशों का की पालना करने हेतु सभी बैंक अधिकारियों व फिनटेक कंपनियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इसके अलावा, उन्होंने

साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जानकारी देने की भी अपील की। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव ने रिज़र्व बैंक की नई नीति, साइबर धोखाधड़ी होने पर सिस्टम और प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया और सभी बैंकों को इसके दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा। इस दौरान आरबीआई से अधिकारी पारुल ने साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त फर्जी बैंक खातों की पहचान के लिए तैयार किये गए कृत्रिम मेधा आधारित **Mulehunter** सॉफ्टवेयर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इसकी मदद से फर्जी बैंक खातों की 90 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ पहचान करना संभव है।

****